Coal for Private Power PJants in Nagpur

*73. SHRI G. PRATHAPA r>DY :
DR. SHRIKANT RAM-

Will the Ii of COAL be pleased to slate :

(a) whetiier the Western Coalfields Ltd. or Coal India Ltd. will supply adequate coal to a private Power Plant if it is set up in Nagpur;

(b) what is the exact policy for supplying coal to Private power plants; and

(c) what are the private po plants in Maharashtra for which Government have received application for the supply of coai ?

THE MINISTER 1 OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) (b) According to the policy of the Government long-term coal lini are given to thermal power plants on the basis of recommendations of Ministry of Power/Central Electricity Authority. This is uniformly applicable to public sector as well as private sector. The question of coal supply to new private power plant in Nagpur can only be examined on the basis of a specific pro and when received.

(c) Long-term coal linkages to the following private sector thermal plants proposed to be located Maharashtra have been indicated:—

(1) Dahanu TPS 2x250 MW

(2) Bhadravati TPS 1000 MW

(3) Wani-Warora TPS 500 MW

In case of Bhadravati TPS interim linkage has been indicated for a period of two years and for the purpose of long-term supply of coal captive coal mines will be developed *by* the power company.

न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति

*74. श्री राम जेठमलानी :,
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार समितियों का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी समितियों का गठन किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछक वर्षों में इन समितियों ने न्यूनतम मजूरी और वेतन के संबंध में अनेक सुझाव दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन सुझावों पर क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :

(क) से (घ) भारतीय श्रम सम्मेलन, 1985 की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 1987 में छः क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां गठित की थीं। समितियों की रचना नीचे दर्शायी गयी है :

क्षेत्र	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1. पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
2. उत्तर पूर्व क्षेत्र	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
3. दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्ष्यद्वीप
4. उत्तरी क्षेत्र	पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़

क्षेत्र	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
5. पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमण, व द्वीप, दादर एंव नगर हवेली
6. मध्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

मध्य क्षेत्र को छोड़ सभी क्षेत्रों से संबंधित इन समितियों की बैठकों का पहला दौर 1987-1990 के दौरान आयोजित किया गया था। समितियों की बैठकों का दूसरा दौर पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का 29 से 30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में, दक्षिणी क्षेत्र का 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में तथा मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों का 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में आयोजित किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र संबंधी समिति की बैठक दिसम्बर, 1994 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम दौर और साथ ही साथ दूसरे दौर की बैठकों ने न्यूनतम मजदूरी संबंधी अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें एक ही क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ते के प्रावधान का प्रावधान जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध विशेष भत्ते का प्रावधान नहीं है वहां दो वर्षों के अंतराल में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दण्डिक उपबन्धों में वृद्धि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में बेहतर अंतर राज्य समन्वय आदि सम्मिलित है। इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

ifoa-ore export to Japaa

SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the export of iron-ore to Japan ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) At present i Iron ore is being exported to Japan I by MMTC and KIOCL under a 5 year contract. Iron ore of Goan origin, being decanalised, is also ex-j ported to Japan by private sector producers.

Cheating consumers by printing in- flated maximum retail prices

H76. SHRI O. P. KOHLI : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) Whether the maximum retail price printed on a product is highly inflated figure having no relevance with the reasonable price of the product consequent to which the consumers are being cheated UH^{S} batedly by the manufacturers and retailers;

(b) if so, what steps Govern- ment propose to take or have taken to suitably safeguard the interests of consumers at the hands of such manufacturers and retailers;

(c) whether there is any proposal to review the provision of the Weights and Measures Act to specify the maximum retail prii

(d) if so, the details there of and the action taken thereon ;

(e) whether there is also any pro posal to print the ex-factory price on the packaged coiumpdities and cloth to safeguard the interests of i consumers; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) The Ministry's attention has been drawn to some reports stating